महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

CORONA SE MAT DARONA

WASH YOUR HAND RREQUENTLY WITH SOAP AND WATER

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-2 • 10 MARCH TO 16 MARCH 2021 • VOLUME-32 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE CONSULTING DESIGN TRAINING

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

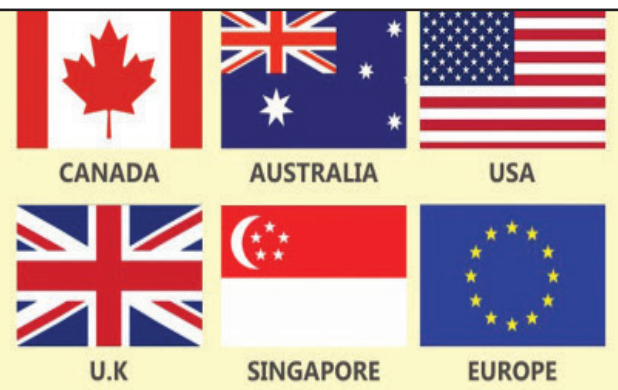

STUDY, WORK & SETTLE IN ABROAD

Low Filing Charges &

*Pay money after the visa

IELTS | STUDY ABROAD

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. • HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

*T&C apply

मनोहर जीत : हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव धराशायी

• नई दिल्ली, ब्यूरो

छह घंटे की लंबी चर्चा के बाद सरकार के खिलाफ लाया गया कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव धराशायी हो गया। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार को 55 विधायकों का साथ सदन में मिला। वहीं 32 विधायकों ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मत किया। अविश्वास प्रस्ताव गिरते ही कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी शुरू कर दी।

इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महाभारत से जुड़ी एक कहानी भी सुनाई। वहीं हुड्डा ने भी सीएम की कहानी का जवाब दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस के अहसानमंद हैं। उन्हें अपनी छह साल की सरकार का लेखा-जोखा रखने का मौका मिला। सत्ता को लेकर कांग्रेस की मृगतृष्णा। इसमें पानी नहीं रेत ही मिलेगी।

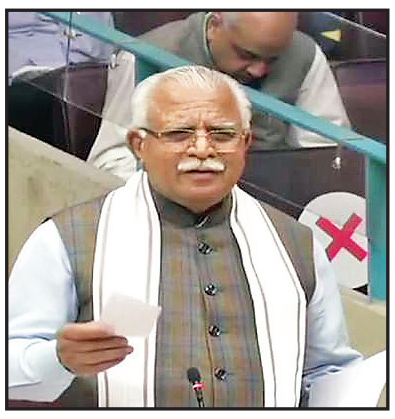

सीएम ने कहा विपक्ष का विश्वास तो कभी नहीं मिलेगा, हमें तो जनता का विश्वास जीतना है। आप एक लोकतांत्रिक रिकॉर्ड बनाइये और हर छह महीने में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइए। इस बार तो आपने मान लिया है कि सरकार के पास बहुमत है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शायराना अंदाज में कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अविश्वास वाली शैली उसे कोई लाभ नहीं देने वाली। कांग्रेस को हर बार अविश्वास होता है, चाहे वो सरकार हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस को कोरोना वैक्सीन पर अविश्वास है। कांग्रेस को इस संस्कृति को बदलना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के बयान का उल्लेख करते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को उत्तर भारतीयों पर भी अविश्वास है। अविश्वास इतना हो गया कि आज के इस प्रस्ताव को लाने का कोई मतलब नहीं था फिर भी लाये। जबकि, इससे कुछ निकलने वाला नहीं था। सरकार को गिराने की स्थिति में होते तो ले आते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष को इस प्रस्ताव से खुश होने की जरूरत नहीं। हमारा जनता के साथ विश्वास बना है। कांग्रेस की स्थिति बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली है।

सीएम ने कहा कि एपीएमसी एक्ट के सेक्शन 42 खत्म करने में हमें आपत्ति नहीं। अगर किसान कोर्ट के पचड़ों में फंस जाएंगे तो दीवानी मुकदमे कितने लंबे चलते हैं आपको पता है। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है, जिससे किसान का हित हो। अगर सेक्शन 42 हटाना है या 8ए हटाना है तो हटाने को तैयार, पूरा सदन एकमत होना चाहिए। इसमें कानून के जानकार सदस्यों की एक कमेटी बना देते हैं। उसमें सरकार प्रस्ताव लाकर नई व्यवस्था 15-16 मार्च तक लागू कर देगी। सीएम के इस प्रस्ताव पर हुड्डा ने कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं। प्रदेश हित में सरकार के साथ हैं।

पीसी चाको ने छोड़ी कांग्रेस, सोनिया को भेजा इस्तीफा

नई दिल्ली, ब्यूरो : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि पीसी चाको ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा है। पीसी चाको दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं। हालांकि 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत नहीं दिला पाने की वजह से उन्होंने प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया था। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पीसी चाके ने कहा कि मैंने कांग्रेस छोड़ दी है और पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। बता दें कि सत्तर पार कर चुके पीसी चाको विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर प्रदेश कांग्रेस ने वरिष्ठतम नेताओं को चुनाव नहीं लड़ाने का फैसला किया है। इसकी वजह से चाको की चुनाव लड़ने की उम्मीदों पर पानी फिर गया और उन्होंने नाराज होकर यह फैसला किया। संप्रग सरकार के समय टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए बनी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के तौर पर भी चाको सियासी चर्चा में रहे थे।

विधायक दल की बैठक में लगी मुहर

उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे तीरथ सिंह रावत

देहरादून : उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें मुख्यमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के उत्तराखंड के सीएम पद से इस्तीफे के बाद अब यह चर्चा तेज थी कि राज्य का अगला सीएम आखिर कौन होगा।

अब तीरथ सिंह रावत के नाम पर मोहर लग गई है। उत्तराखंड के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम समेत सभी सांसद और विधायक बैठक में मौजूद थे। देहरादून के बीजेपी ऑफिस में हुई बैठक में पूर्व सीएम रावत भी मौजूद रहे। जिक्रयोग्य है कि तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से बीजेपी सांसद हैं। 2000 में तीरथ सिंह रावत नवगठित उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री बने। वहीं साल 2007 में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री चुने गए। वह राज्य चुनाव अधिकारी और प्रदेश सदस्यता प्रमुख भी रह चुके हैं।

आयुष्मान भारत योजना : निजी अस्पतालों द्वारा करोड़ों की घपलेबाज़ी का पर्दाफ़ाश

• जालंधर ब्रीज.ब्यूरो

पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने राज्य के कुछ प्राईवेट अस्पतालों द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के अधीन लाभार्थियों का इलाज करने के नाम पर फर्जी डॉक्टरी बिलों के द्वारा प्रतिपूर्ति के दावों में करोड़ों रुपए की घपलेबाज़ी करके मोटी रकमों के बीमा क्लेम हासिल किए जाने का पर्दाफाश किया है।

इस दौरान अधिकृत इफको टोकियो बीमा कंपनी द्वारा सरकारी अस्पतालों के बीमा क्लेम भारी मात्रा में रद्द कर दिए गए, जिस कारण राज्य सरकार के खज़ाने को करोड़ों का घाटा पड़ा है।

बुधवार को यह जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के मुख्य डायरैक्टर और डी.जी.पी. बी.के. उप्पल ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना में चल रहे इस घोटाले की हर पक्ष से गहराई तक जांच करने एक विजीलैंस इंक्वायरी दर्ज की गई है, जिससे इस योजना के अधीन प्राईवेट अस्पतालों द्वारा की जा रही बड़ी घपलेबाज़ी करके अपने आप को वित्तीय लाभ पहुँचाने सम्बन्धी की जा रही अनियमितताओं का पर्दाफाश किया जा सके और सरकारी अस्पतालों के बीमा क्लेम रद्द करने के कारणों की जांच हो सके।

उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में दलजिन्दर सिंह ढिल्लों एस.एस.पी. विजीलैंस ब्यूरो, जालंधर रेंज जालंधर द्वारा एकत्रित की गई प्राथमिक चांज के अनुसार आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत जालंधर, होशियारपुर और कपूरथला के कई बड़े नामी अस्पतालों द्वारा स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड धारकों के नाम पर मोटी रकमों के फर्जी डॉक्टरी बिल तैयार करके बड़े स्तर पर घपलेबाज़ी करके बीमा क्लेम हासिल किए जा रहे हैं। इन तीन ज़िलों में कुल 35 सरकारी अस्पताल और 77 प्राईवेट अस्पताल इस योजना के अधीन राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं।

...शेष- पेज 4 पर

विधायक खैहरा की रिहायश पर ई.डी. द्वारा रेड की निंदा

• स्टेट ब्यूरो, चंडीगढ़

पंजाब विधान सभा ने बुधवार को बजट सैशन के दौरान सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके विधायक खैहरा की रिहायश पर ई.डी. द्वारा की गई रेड की आलोचना करते हुए इसको गैर-कानूनी और अनुचित बताया है।

संसदीय मामलों संबंधी मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने बताया कि सदन ने केंद्रीय एजेंसियों जैसे सी.बी.आई., ई.डी., एन.आई.ए. आदि का प्रयोग किसानों, राजनैतिक तौर पर चुने हुए प्रतिनिधियों और यहां तक कि कुछ सरकारी अधिकारियों समेत निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए किये जाने के विरुद्ध एकसुर में आवाज उठाते हुये इस मुद्दे पर चिंता जाहिर की जबकि यह एजेंसियाँ सार्वजनिक जिंदगी में पारदर्शिता को यकीनी बनाने के लिए हैं।

संसदीय मामलों संबंधी मंत्री ने कहा कि पंजाब विधान सभा के चल रहे सैशन के दौरान सदन के मैंबर सुखपाल सिंह खैहरा को सदन की कार्यवाही में गैर-हाजिर रहने के लिए मजबूर किया गया और प्रवर्तन निदेशालय की अनुचित और गैर-कानूनी दख़लअन्दाजी के कारण उनको हलके के चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाने से रोका गया, जिसका सदन द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके नोटिस लिया गया है। केंद्रीय एजेंसियों के गैर-कानूनी और अनुचित प्रयोग की निंदा करते हुए सदन ने भारत सरकार से अपील की कि वह कानून की निर्धारित प्रक्रिया को तोड़ कर लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकारों का उल्लंघन करने से गुरेज़ करें।

पालना

पंजाब एंड हरियाणा

हाईकोर्ट द्वारा चीफ सेक्रेटरी को दिए गए निर्देशों की पालना नहीं करवा पा रहे निचले स्तर के अफसर

• पंजाब के लोक निर्माण विभाग (बीएंडआर) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो व राजमार्गों से जुड़ती लिंक रोड पर भी लगाएं जाए इसी प्रकार के रम्बल स्ट्रिप्स व स्पीड ब्रेकर, तभी दुर्घटनाएं कम हो पाएंगी।

• **जालंधर ब्रीज.** विशेष रिपोर्ट

पंजाब में सड़क सुरक्षा को लेकर कुछ महीनों पहले अलग-अलग विभागों द्वारा सड़क हादसों के दौरान मानव जीवन को बचाने के लिए और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कई तरह के सेमीनार, वर्कशॉप और जागरूकता कैंप लगाए गए थे। इस दौरान सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित सभी विभागों को सड़क पर हो रहे हादसों को टालने के लिए पंजाब से गुजरते राष्ट्रीय राजमार्गों और राज मार्गों पर ब्लैक स्पॉटों की पहचान करके उन्हें सुधारने के निर्देश ट्रांसपोर्ट मंत्री रज़िया सुलताना द्वारा दिए गए थे।

लेकिन साल 2014 में पंजाब के मुख्य सचिव द्वारा माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा पास किये गए आर्डर की पालना करने के लिए सभी विभागों के मुखियों की मीटिंग रखी गई थी। जिसमें लोक निर्माण विभाग (बीएंडआर) और नेशनल हाईवे विभाग को सड़क सुरक्षा को लेकर पाई गई कमियों की रिपोर्ट नोडल ऑफिसर्स को सौंपने के लिए कहा गया था और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि राष्ट्रीय राजमार्गों के ऊपर चढ़ने से पहले सभी लिंक रोड्स के ऊपर लोक निर्माण विभाग द्वारा स्पीड ब्रेकर्स या रम्बल स्ट्रिप्स लगाने अनिवार्य होंगे ताकि कोई भी फोर व्हीलर या टू व्हीलर वाहन लिंक रोड पर ही अपनी स्पीड को कम कर पाए जिससे की राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्विस लेन या मुख्य सड़क पर चल रहे वाहनों की लिंक रोड से आ रहे वाहनों के साथ आपस में भिड़ंत न हो पाए लेकिन पंजाब के ज्यादा तर लिंक रोड्स के ऊपर लोक निर्माण विभाग द्वारा स्पीड ब्रेकर्स या रम्बल स्ट्रिप्स नहीं लगाए गए हैं जिसके कारण हर समय किसी न किसी व्यक्ति या वाहनों का आपस में टकराव हो जाता है या होने की स्थिति पैदा हो जाती है।

पीडब्ल्यूडी बीएंडआर पंजाब

इस मीटिंग दौरान एक स्टेट लेवल टास्क फॉर्स भी गठित की गयी थी जिसमें वन विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग , लोक निर्माण विभाग (बीएंडआर) और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (ट्रैफिक) को शामिल किया गया था। इन सबको हर तीन महीने बाद मीटिंग में जारी की गई हिदायतों की पालना हो इसके लिए रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था और साथ में हिदायत दी गई थी कि जो निर्देश माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा पास किए गए है, उन्हें संबंधित विभागों से पूरा करवाया जाए और पंजाब लोक निर्माण विभाग (बीएंडआर) के चीफ इंजीनियर को हर तीन महीने बाद होने वाली स्टेट लेवल टास्क फॉर्स की मीटिंग का संयोजक बनाया गया था। लेकिन लोक निर्माण विभाग द्वारा लोगों को सड़क सुरक्षा देने के लिए जो वादे किये जा रहे हैं वो अभी तक सब खोखले साबित हुए हैं। क्यों नहीं लोक निर्माण विभाग (बीएंडआर) के चीफ इंजीनियर द्वारा पंजाब के राष्ट्रीय राजमार्गों और राजमार्गों व उनसे जुड़ती लिंक रोड्स पर स्पीड ब्रेकर्स या रम्बल स्ट्रिप्स सख्ती से लगवाएं जा रहे हैं जिससे दुर्घटना व मानवीय नुकसान से बचा जा सके।

उधर, माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उसकी पालना भी यकीनी बनाई जा सके तभी जा कर सड़क हादसों और उस दौरान होने वाली मौतों में पंजाब के अंदर कमी आएगी।

महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा डिप्रेशन का खतरा!

डिप्रेशन

महिलाओं में डिप्रेशन के लक्षण पुरुषों की अपेक्षा बहुत अलग होते हैं। ऐसे में इन लक्षणों को सही समय पर भांपना बहुत जरूरी है। अवसाद में महिलाओं के साथ अक्सर मूड स्विंग की समस्या होती है यानी बहुत जल्दी-जल्दी उनका मूड बदल जाता है। कई बार मूड इस कदर बदलता है कि उन्हें घबराहट के दौरे तक पड़ने शुरू हो जाते हैं। इस स्थितिमें अवसाद की वजह कोई विशेष परिस्थिति, हार्मोन की गड़बड़ी या फिर एलर्जी भी हो सकती है। अवसाद की स्थिति में कई बार हर बात से रुचि खत्म होने लगता है। महिलाएं अपनी दिनचर्या या आस-पास के लोगों में रुचि कम कर देती हैं। कई बार अवसाद की वजह से वे किसी भी बात पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पातीं और बात-बात पर अपना आपा खोने लगती हैं। कई बार अवसाद की स्थिति में महिलाओं की डाइट प्रभावित होती है। अच्छा महसूस करने के लिए वे बहुत अधिक खाती हैं या फिर अवसाद में दुखी होकर भोजन ही नहीं करतीं। दोनों परिस्थितियों में अवसाद का प्रभाव डाइट पर हो सकता है।

खासतौर पर महिलाओं पर अवसाद के दो तरह से प्रभाव पड़ते हैं, या तो उन्हें नींद नहीं आती या फिर नींद बहुत अधिक आती है। तो अगर सोने में उन्हें इस तरह की समस्या हो तो इसे अवसाद के लक्षण मान सकते हैं। दिन भर घर-बाहर की भागदौड़ में मुस्कराने वाली महिलाएं हमेशा थकी-थकी दिखें तो समझिए कि उनके साथ जरूर कोई दिक्कत है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि हम अगर डिप्रेशन जैसे लक्षणों को महसूस करते हैं तो उसके बारे में खुलकर बात करने और इसके संकेतों तथा लक्षणों को बेहतर तरीके से समझकर, खुद की अच्छे ढंग से मदद कर सकते हैं। डिप्रेशन हालांकि सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित करता है लेकिन ज्यादातर किशोरों और युवाओं, प्रसव की आयु वाली महिलाओं तथा 60 वर्ष की उम्र से ऊपर के लोगों में आमतौर से पाया गया है। जहां तक अवसाद के लक्षणों की बात है, पीड़ित व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती है, कम भूख लगती है, अपराध बोध होता है, आत्मविश्वास में कमी रहने लगती है, थकान और सुस्ती महसूस होती है। उत्तेजना या शारीरिक व्यग्रता बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को नियमित रूप से ऐसे व्यक्तियों से बातचीत करती रहने चाहिए, जिन पर वे भरोसा करते हों या जो उनके सबसे अधिक प्रिय हों। अवसादग्रस्त व्यक्ति को शराब और नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। हर समय थकान लगना भी अवसाद का एक गंभीर लक्षण है।

अवसाद से घिरी महिलाएं अक्सर अपनी ही आलोचना करती हैं। बीते समय में जो हुआ अक्सर उन बातों को याद करके खुद को कोसती हैं। उन्हें हमदर्दी की तलाश होती है जिनसे वे अपने अंदेशे साझा कर सकें। अवसाद जब बहुत अधिक प्रभावित कर देता है तो मन में आत्महत्या तक करने का विचार आ सकता है। उन्हें अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं दिखता। इस स्तर तक उनका अवसाद पहुंचे इससे पहले उन्हें चिकित्सा की बहुत जरूरत है।

अपने दुख का ताड़ बनाना

हमें हर छोटी सी समस्या बड़ी दिखती है। हर समय दिमाग अतीत की गलियों में घूमता रहता है। ऐसे में जितना हम अपने दुख दूसरों के सामने रखते हैं, उतने ही नकारात्मकता और दुखों की ओर बढ़ जाते हैं।

जीवन के सुख-दुख को देखने का हमारा चश्मा अलग-अलग होता है। दूसरों के सुख बड़े लगते हैं तो अपने दुख। अपने छोटे से छोटे दुख को गाने की ऐसी लत लगती है कि मानो एक हम ही हैं जो दुखों को झेल रहे हैं। बात यहीं तक नहीं रुकती, हम केवल यह नहीं चाहते कि लोग हमारे दुख को सुनें, हम उनकी सहानुभूति का फायदा भी उठाना चाहते हैं। अपने दुखों की आड़ में अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं।

'मैंने जिंदगी देखी है', 'तुम्हें क्या पता दुख क्या होता है', 'मेरी किस्मत में सुख कहां', ऐसी ही कई बातें कहते हुए हम बिल्कुल दार्शनिक हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानी, जिन्हें अपना राई बराबर दुख पहाड़ नजर आता है। हो सकता है कि आपके पास संसाधनों की कमी हो, बीमारी या परिवार की उपेक्षा झेल रहे हों, पर यह सच है कि संघर्ष सबके जीवन में होता है। लेकिन व्यक्ति के सहने की क्षमता और प्रवृति के आधार पर इसका अनुभव हर किसी को अलग होता है।

फैमिली थेरेपिस्ट और लेखिका इजाडोरा एल्मन कहती हैं, 'अपने दुख दूसरों को बताना मन की सेहत के लिए अच्छा होता है। पर उसकी नुमाइश करना या अपने दुख से लाभ कमाने की कोशिश करना, व्यक्तित्व की कमजोरी है। मन की हीनता और दुर्बलता है। यह दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति है। मेरा अनुभव कहता है कि अपने दुख में मदद चाहिए तो बात को सीधे और स्पष्ट ढंग से सही लोगों के सामने कहें, वरना हर समय सहानुभूति हासिल करने की लत नुकसान ही पहुंचाती है।'

नमक जैसा है दुख : एक बूढ़ा जेन मास्टर अपने शिष्य की शिकायत करने की आदत से परेशान था। एक सुबह उन्होंने शिष्य को कुछ नमक एक गिलास पानी में मिलाकर पीने को दिया। मास्टर ने पूछा- कैसा है यह? शिष्य ने कहां, यह कड़वा लग रहा है, इसे पीना असंभव है। इसके बाद वे दोनों झील के किनारे गए। मास्टर ने उतना ही नमक झील के पानी में डाल दिया। शिष्य को फिर पानी पीने के लिए कहा और पूछा कि अब ये कैसा लग रहा है? शिष्य ने कहा, ये पानी बिल्कुल ताजा है। इसमें नमक का पता ही नहीं चल रहा। मास्टर ने कहा, जीवन में दुख भी नमक की तरह है। इसकी मात्रा भी समान ही है। पर इसकी कड़वाहट निर्भर करती है कि हमने इसे किस बर्तन में डाला है। जब दुख हो तो शिकायत की जगह अपने नजरिए को बड़ा कर लेना चाहिए।

अच्छी नहीं दुख की लत : सेल्फ इंप्रूवमेंट वेबसाइट 'द इमोशनल मशीन' में स्टीवन हैंडल कहते हैं, दुखों की निरंतर चर्चा करना हमें अपने नकारात्मक अनुभवों से बाहर नहीं आने देता। हमें हर छोटी सी समस्या बड़ी दिखती है। हर समय दिमाग अतीत की गलियों में घूमता रहता है। ऐसे में जितना हम अपने दुख दूसरों के सामने रखते हैं, उतने ही नकारात्मकता और दुखों की ओर बढ़ जाते हैं।

दुखों पर बात करने का सही तरीका

' सबके सामने अपना दुख को बोझ हल्का न करें। ऐसे लोगों से बातें करें, जो आपको सुनने को तैयार हैं।

' यदि सलाह व मदद की जरूरत है तो सीधा कहें। बढ़ा-चढ़ाकर बातें न करें। नाटकीय होने से बचें।

' मजाक का साथ न छोड़ें। खुद पर हंसें। दुख के प्रति गंभीर बने रहना तनाव बढ़ाता है। व्यावहारिक बनें। दुख को स्वीकार करें।

' संतुलन की ओर बढ़ें। बातें करें, पर ध्यान रखें कि समस्याओं पर बात करने का एक सही समय और जगह होती है।

मनुष्य के लिए विवेक सबसे अच्छा गुण

ज्ञान

विवेक ही वासनायुक्त अज्ञानी जीव को ज्ञान प्रदान करता है। ज्ञानस्वरूप आत्मा ही सबसे बड़ा परमेश्वर है।

भगवान श्रीराम समय-समय पर अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर उनका सत्संग सुना करते थे। एक दिन सत्पुरुषों के सत्संग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महर्षि वशिष्ठजी ने कहा- 'रघुकुल भूषण राम! जिस प्रकार दीपक अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार विवेक-ज्ञान संपन्न महापुरुष हृदय में स्थित अज्ञानरूपी अंधकार को सहज ही में हटा देने में सक्षम होते हैं। इसलिए सभी धर्मग्रंथों में प्रतिदिन किसी-न-किसी सत्पुरुष के सत्संग तथा शास्त्रों के स्वाध्याय पर बल दिया गया है।'

महर्षि वशिष्ठ ने अपने शिष्य श्रीराम से आगे कहा- 'विवेकी महापुरुष इंद्रियनिग्रही, परम विरक्त तथा हर क्षण ब्रह्मा का चिंतन करने वाले होते हैं। जिनमें तमोगुण का सर्वथा अभाव है, जो रजोगुण से रहित हैं, जिनमें संसार के प्रति वैराग्य सुदृढ़ हो जाता है, ऐसे सत्पुरुषों का सान्निध्य बड़े भाग्य और पुण्य से प्राप्त होता है। उनका सान्निध्य पाते ही सभी सांसारिक भोगों की तृष्णा नष्ट हो जाती है। आनंदस्वरूप आत्मा की अनुभूति हो जाने से साधक धन-संपत्ति, भोग-वैभव त्याग देने को सहज ही तत्पर हो जाता है।'

भगवान श्रीराम ने पूछा- 'गुरुवर, ऐसे महापुरुष का सर्वोत्कृष्ट गुण क्या होता है?' महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया- 'उसका नाम है विवेक। विवेक मनुष्य की हृदयरूपी गुफा में ऐसे स्थित हो जाता है, जैसे निर्मल आकाश में चंद्रमा। विवेक ही वासनायुक्त अज्ञानी जीव को ज्ञान प्रदान करता है। ज्ञानस्वरूप आत्मा ही सबसे बड़ा परमेश्वर है। ज्ञानरूपी चिदात्म सूर्य का उदय होते ही संसार रूपी रात्रि में विचरता हुआ मन रूपी पिशाच नष्ट हो जाता है।'

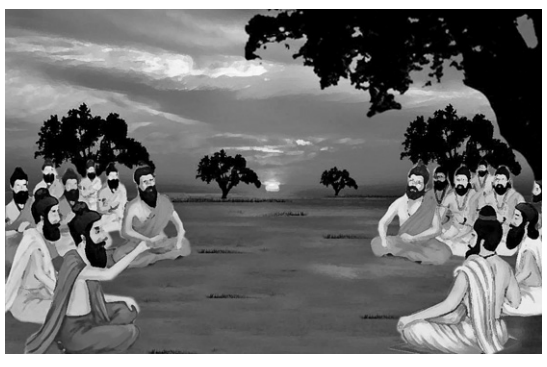

लिव-इन में रहने वाली महिलाओं को बरतनी होंगी सावधानियां

वरना नहीं मिलेगा संपत्ति में कानूनी अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को भले ही कानूनी कवच पहना दिया हो, लेकिन लिव इन में रहने वाली महिला अपने पुरुष पार्टनर की संपत्ति में किसी भी तरह का कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता है।

शादी के बंधन में बंधे बिना पति-पत्नी की तरह रहने वाले यानी लिव-इन रिलेशन में रहने का चलन तेजी से बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कानूनी मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि लिव-इन रिलेशनशिप न अपराध है, और न ही पाप, शादी करने या न करने और सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का फैसला पूरी तरह से निजी है। लिहाजा 18 की उम्र पूरी कर चुकी लड़की और 21 की उम्र पूरी कर चुका लड़का लिव-इन में रह सकते हैं। शीर्ष कोर्ट ने लिव-इन को कानूनी कवच जरूर पहना दिया है, लेकिन लिव-इन पार्टनर को आज भी वो पूरे कानूनी अधिकार नहीं मिलते हैं, जो एक शादीशुदा महिला को अपने पति की संपत्ति में मिलते हैं। इसके चलते कई बार महिला लिव-इन पार्टनर को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष का कहना है, कि भारत में लिव-इन को बेहद लूज रिलेशनशिप माना जाता है। शादीशुदा महिला को जितने कानूनी अधिकार मिलते हैं, उतने लिव-इन में रहने वाली महिला को नहीं मिल पाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि लिव-इन में रहने वाले लोगों के लिए अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप होने की बात साबित करना बेहद मुश्किल होता है। अगर परिस्थिति जन्य साक्ष्य यानी रेंट एग्रीमेंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, पार्टनरशिप बिजनेस के दस्तावेज या फिर बायलॉजिकल चाइल्ड के जरिए लिव-इन में होने की बात साबित भी हो जाती है, तो भी लिव-इन में रहने वाली महिला को पार्टनर की संपत्ति में कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता है। हालांकि महिला लिव-इन पार्टनर से गुजारा भत्ता के लिए दावा कर सकती है।

महिला लिव-इन पार्टनर को सिर्फ गुजारा भत्ता मिल सकता है

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 के तहत महिला लिव-इन पार्टनर भी शादीशुदा पत्नी की तहत गुजारा भत्ता मांग सकती है। यह दावा सिर्फ पुरुष लिव-इन पार्टनर के जीवित रहने पर ही किया जा सकता है। अगर पुरुष लिव-इन पार्टनर की मौत हो जाती है, तो महिला पार्टनर को गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भी महिला लिव-इन पार्टनर गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है।

विदेश में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जागरूक : अगर कोई महिला विदेश में लिव-इन रिलेशनशिप में रहती है, तो उसको वहां के स्थानीय कानून के तहत अधिकार मिलते हैं। हर देश में इसको लेकर अलग-अलग कानून हैं। इससे भी अहम बात यह है कि विदेश में लिव-इन में रहने वाले लोग अपने कानूनी अधिकार को लेकर बेहद अलर्ट रहते हैं। हालांकि भारत में लिव-इन में रहने वाले लोग अपने कानूनी अधिकार को लेकर काफी लापरवाही बरतते हैं, जिसके चलते कई बार उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

कैसे मिलेगा लिव-इन पार्टनर की संपत्ति में हक : सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जितेंद्र मोहन शर्मा ने कहा कि अगर लिव-इन में रहने वाली महिला अपने पार्टनर की संपत्ति पर कानूनी अधिकार चाहती है, तो उसको अपने नाम वसीयत करा लेनी चाहिए। वरना लिव-इन में रहने वाली महिला को अपने लिव-इन पार्टनर की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। इसके अलावा महिला को इंश्योरेंस पॉलिसी में लिव-इन पार्टनर के नॉमिनी के रूप में खुद को दर्ज करवाना चाहिए। जितेंद्र मोहन शर्मा का यह भी कहना है कि लिव-इन में रहने वाले एग्रीमेंट के जरिए भी लिव-इन पार्टनर की संपत्ति में हक हासिल कर सकते हैं। इसके लिए लिव-इन में रहने वालों को रजिस्ट्रार ऑफिस में एग्रीमेंट का पंजीकरण करवा लेना चाहिए। इस एग्रीमेंट में संपत्ति के हक को लेकर स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

लिव-इन में जन्मे बच्चों को मिलते हैं पूरे कानूनी अधिकार : लिव-इन में रहने वाली महिला को लिव-इन पार्टनर की संपत्ति पर भले ही कोई कानूनी अधिकार न मिले, लेकिन उनकी बायोलॉजिकल संतान को पूरे अधिकार मिलते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लिव-इन से जन्मे बच्चे को वो सभी कानूनी अधिकार मिलते हैं, जो शादीशुदा दंपति से जन्मे बच्चे को मिलते हैं। उनका कहना है कि लिव-इन से जन्मा बच्चा अपने बायोलॉजिकल पिता की संपत्ति में हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत हिस्सा हासिल कर सकता है।

प्लास्टिक का इस्तेमाल आपको कर सकता है बीमार

बिस्फिनॉल (बीपीए): बीपीए का इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। यह प्लास्टिक फूड कंटेनर्स, वॉटर बॉटल्स और पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल करनेवाले कंटेनर्स में लाइनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी): यह फूड पैकेजिंग से लेकर, बच्चों के खिलौनों, शावर कर्टन्स, बिल्डिंग मटेरियल्स आदि में इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक में मौजूद पीवीसी भ्रूण के विकास को प्रभावित करता है। इससे भ्रूण का रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रभावित होता है। इसलिए गर्भवती व ब्रेस्टफीडिंग महिलाओं को कम से कम प्लास्टिक के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है।

बीपीए के साइड इफेक्ट्स : कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीपीए हमारे शरीर में एक हार्मोन की तरह काम करता है, जिससे शरीर में हार्मोंस के असंतुलन की संभावना बढ़ जाती है। इसका सबसे ज़्यादा असर भ्रूण व नवजात बच्चों पर पड़ता है। बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी का ख़तरा बढ़ जाता है और बड़े होने पर उनमें ब्रेस्ट कैंसर व प्रोस्टेट कैंसर का ख़तरा भी होता है।

- इसके कारण छोटी बच्चियों में हाइपर एक्टिविटी या फिर एग्रेसिव बिहेवियर की संभावना भी बढ़ जाती है।
- यूरिन में बीपीए की अधिकता के कारण वयस्कों में कार्डियो वैस्कुलर डिसीज़ का ख़तरा अन्य लोगों के मुक़ाबले तीन गुना बढ़ जाता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा दोगुना हो जाता है।

- कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि बीपीए के कारण ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और ओवेरियन कैंसर का ख़तरा भी बढ़ जाता है, पर फ़िलहाल इस विषय पर अधिक रिसर्च जारी है।
- प्लास्टिक कंटेनर्स में खाना गर्म करने से प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स के कुछ तत्व खाने में मिल जाते हैं, जिसके कारण लंबे समय तक इनका इस्तेमाल कैंसर का कारण बन सकता है।

पीवीसी के साइड इफेक्ट्स

- ये शरीर में मौजूद एस्ट्रोजेन और थायरॉइड हार्मोंस को प्रभावित करते हैं।
- ये बच्चों के विकास को बाधित करते हैं, जिससे बचपन में ही वे कुछ ऐसी समस्याओं के शिकार हो जाते हैं, जो उनके शारीरिक व मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं।
- इसका प्रभाव महिलाओं व पुरुषों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप पुरुषों में जहां स्पर्म काउंट कम हो जाता है, वहीं महिलाओं में ओवम की क्वालिटी पर असर पड़ता है।
- इससे लिवर कैंसर व किडनी ख़राब होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है।

प्लास्टिक की दुनिया

प्लास्टिक वॉटर बॉटल : प्लास्टिक से बनी पानी की बॉटल्स में बीपीए मौजूद होता है, जिसके लगातार इस्तेमाल से गर्भवती महिलाओं और भ्रूण में क्रोमोज़ोमल एब्नॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। महिलाओं व पुरुषों की फर्टिलिटी को प्रभावित करता है। इन एब्नॉर्मलिटीज़ के कारण बच्चा जन्मजात दोषों का शिकार हो सकता है। बीपीए के कारण होनेवाले सभी साइड इफेक्ट्स प्लास्टिक की बॉटल से पानी पीनेवालों को हो सकते हैं।

दूध की बॉटल्स व सिपर्स : पहले जहां दूध की बॉटल्स स्टेनलेस स्टील की होती थीं, आज उनकी जगह प्लास्टिक की बॉटल्स ने ले ली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंवायरन्मेंटल हेल्थ साइंसेज़ के अनुसार प्लास्टिक की इन बॉटल्स में बीपीए होता है, जो नवजात बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। दूध की बॉटल्स को उबलते पानी में डालकर ना रखें, इससे प्लास्टिक केमिकल्स बाहर निकलने लगते हैं, जो बच्चे के लिए नुक़सानदायक साबित होगा।

प्लास्टिक कंटेनर्स : ज़्यादातर माइक्रोवेव कंटेनर्स प्लास्टिक से बने होते हैं और रिसर्चर्स का मानना है कि कंटेनर के गर्म होने पर कुछ तत्व खाने में मिल जाते हैं, जिनका लंबे समय तक इस्तेमाल कई तरह के कैंसर समेत विभिन्न हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। इनमें भी बीपीए का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो भी साइड इफेक्ट्स उससे जुड़े हैं, उनके होने का ख़तरा बढ़ जाता है।

सांझ हेल्प डैस्क और '181' हेल्पलाइन पंजाब की महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को बनाएंगे और अधिक सुरक्षित

• जालंधर ब्रीज.रिपोर्टर

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई अनूठी सांझ शक्ति पहलकदमी से अब पंजाब में महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक अपराध, शोषण या घरेलू हिंसा के किसी भी अपराध की रिपोर्ट '181' पर कॉल करके कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा सोमवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य के सभी 382 पुलिस स्टेशनों में साझ शक्ति हेल्प डैस्क स्थापित किए गए, इसके साथ ही सांझ शक्ति हेल्पलाइन '181' भी शुरू की गई। समाज के कमज़ोर वर्गों के सशक्तिकरण और सुरक्षा सम्बन्धी बेमिसाल प्रोजैक्ट शुरू करने के लिए डीजीपी दिनकर गुप्ता के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रयास महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को भरोसे योग्य और उचित माहौल में पुलिस के साथ अपनी चिंताएं और शिकायतें साझा करने में सहायता करेंगे।

डीजीपी गुप्ता ने आगे कहा कि कुल 382 हैल्पडैक्सों में से 266 सांझ केन्द्र कार्यशील हैं, जो थानों के पास ही अलग सांझ केंद्र इमारतों में स्थित हैं, जबकि बाकी के 116 हेल्प डैस्क सांझ केंद्र की इमारतें न होने के कारण पुलिस स्टेशनों में स्थापित किए गए हैं। सांझ केन्द्रों को नया डिज़ाइन और रूप प्रदान किया गया है, जिससे सांझ केन्द्रों में आने वाले शिकायतकर्ताओं को इन केन्द्रों में तैनात पंजाब पुलिस महिला मित्र (पीपीएमएम) या वूमैन पुलिस व फ्रैंड, जो महिलाओं,

बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को शिकायतें और बयान दर्ज करने और कार्यवाही रिपोर्टें तैयार करने में सहायता करते हैं, के साथ बातचीत करते समय बैठने के लिए आरामदायक जगह और भरोसे योग्यता प्रदान की जा सके। हर हैल्पडैस्क पर दो महिलाएं 'पीपीएमएम' तैनात होंगी, जो बयान दर्ज करवाएंगी और रैफरैंस के लिए शिकायतकर्ता को एक विलक्षण पहचान नंबर भी प्रदान करेंगी।

हर शिकायत की निगरानी ए.डी.जी.पी. कम्युनिटी अफेअरज़ डिवीजन एंड वूमैन एंड चाइल्ड अफेअरज़ की तरफ से जाएगी और शिकायतकर्ताओं को उनकी शिकायतों की प्रगति सम्बन्धी जानकारी की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। डीजीपी ने '181' हेल्पलाइन का विवरण देते हुए कहा कि इस सहायता को सेवाओं और कानूनी कार्यवाहियों के लिए सम्मानजनक पहुँच प्रदान करने के लिए सभी हेल्प डेस्कों के साथ जोड़ा जाएगा।

इस हेल्पलाइन पर पुलिस को घरेलू हिंसा, छेड़-छाड़ या अन्य परेशानी आदि की रिपोर्ट करने के अलावा, शिकायतकर्ता साईबर क्राइम जैसे कि तस्वीरों के साथ छेड़छाड़, महिलाओं की नकली प्रोफाइल बनाना, साईबर स्टॉकिंग या सोशल मीडिया, इन्टरनेट या ई-मेल के द्वारा शोषण की रिपोर्ट कर सकता है और अगली जाँच के लिए यह केस राज्य के साईबर क्राइम सैल को भेजे जाएंगे। डीजीपी ने कहा कि 181 हेल्पलाइन पर तैनात पुलिस अधिकारी अपराधियों को बुलाएंगे और उनको कानूनी नतीजों के बारे में चेतावनी देंगे और अगर ऐसा शोषण बंद न हुआ तो शिकायतकर्ता की फीडबैक के बाद कानूनी कार्यवाही भी आरंभ की जाएगी।

कॉल मुख्य तौर पर सॉफ्ट स्किल्ज़ की प्रशिक्षण प्राप्त महिला ऑपरेटरों द्वारा सुनी जाएंगी और फ़ोन करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि शिकायतकर्ता इस हेल्पलाइन पर नशा तस्करी/पैडलिंग संबंधी भी सूचना दे सकते हैं। श्री गुप्ता ने महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उचित वातावरण को यकीनी बनाने के लिए पंजाब पुलिस की वचनबद्धता को दोहराया जिससे वह किसी जुर्म के बारे में सूचना देने में संकोच न करें।

मंगल की सतह पर रेंगा नासा का पर्सिवियरेंस रोवर, 19 दिनों में 21 फीट का सफर किया तय

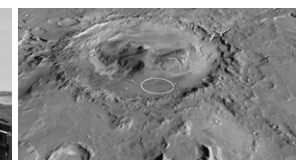

• नई दिल्ली.ब्यूरो

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पर्सिवियरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर चलना शुरू कर दिया है। एक टन वजन वाले रोवर को मंगल ग्रह पर एक लंबा सफत तय करना है, लेकिन उसने 19 दिनों में 6.5 मीटर यानी 21 फीट का ही सफर तय किया है। इस दूरी को तय करने के बाद रोवर 150 डिग्री को मोड़ लिया और वापस अपनी जगह पर लौट आया। वैज्ञानिकों ने उसकी इस गति को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि करार दिया है। एजेंसी की ओर से बताया गया है कि पर्सिवियरेंस करीब दो वर्ष के कालखंड में मंगल सतह पर करीब 15 किलोमीटर तक का सफर तय करेगा।

रोवर मंगल पर मानव जीवन के निशानों की खोज करेगा। इसके साथ यह एक लाख पुरानी सूख चुकी झील की जमीन की जांच करने के साथ अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर माइक्रो ऑर्गानिज्म की किसी भी गतिविधि यानी जीवन के होने के चिन्हों की जांच करेगा।

इस रोवर का एक मकसद मंगल ग्रह पर कम वजन वाले एक हेलिकॉप्टर को भी उड़ाना है। यही वजह है पर्सिवियरेंस अपने साथ एक छोटा सा हेलिकाप्टर लेकर गया है।

रोवर ने भेजी मंगल ग्रह से चौंकाने वाली तस्वीरें : नासा के पर्सिवियरेंस रोवर ने अपना काम शुरू कर दिया है। रोवर ने मंगल ग्रह से चौंकाने वाली तस्वीरें भेजी हैं। उसकी मिमोरी में बहुत सारा डेटा है, जिसको वह धीरे-धीरे धरती पर भेज रहा है। नासा ने कहा है कि वह आने वाले दिनों में और भी कई तस्वीरें जारी करेगा। इन तस्वीरों में रोवर के मंगल ग्रह पर उतरने की छोटी सी मूवी शामिल होगी। खास बात यह है कि मूवी में साउंड भी होगा।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता

• नई दिल्ली.ब्यूरो

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक जुलाई से महंगाई भत्ता का पूरा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सभी तीनों लंबित किस्तों को एक जुलाई से रिस्टोर किया जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री ने मंगलवार को संसद में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनर्स के डीआर की तीन किस्तों को कोविड-19 महामारी की वजह से फ्रीज कर दिया गया था। ये तीन इंस्टॉलमेंट एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को देय थीं। केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा, जिन्हें पुराने दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था।

इसकी वजह यह है कि सरकार ने कोविड-19 महामारी की वजह से नए दर से क्रियान्वयन को टाल दिया था। अमूमन हर वर्ष दो बार (जनवरी और जुलाई में) डीए में संशोधन किया जाता है।

7वां वेतन आयोग

मंत्री ने कहा कि जुलाई, 2021 से डीए और डीआर को रिस्टोर किए जाने से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनधारकों को फायदा होगा।

ठाकुर ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा, "महंगाई भत्ते में संशोधन को डेढ़ साल तक निलंबित रखने से सरकार को 37,530.08 करोड़ रुपये की बचत हुई और इससे कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में मदद मिली।"

वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17 फीसद की दर से डीए मिलता है। महंगाई भत्ता की यह दर जुलाई, 2019 से प्रभावी है।

डीए की दर में अगला संशोधन जनवरी 2020 से प्रभावी होना था लेकिन जनवरी के साथ-साथ जुलाई, 2020 और जनवरी, 2021 में होने वाले संशोधनों को कोविड-19 की वजह से निलंबित कर दिए जाने की वजह से उन्हें अबतक पुरानी दर से महंगाई भत्ता का लाभ मिल रहा है।

पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता को चार फीसद बढ़ाकर कुल 21 फीसद कर दिया था। यह एक जनवरी, 2020 से प्रभावी होना था लेकिन महामारी की वजह से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता और डीआर के भुगतान के फैसले को टाल दिया गया था।

लगभग आधे साल तक पड़ेगी गर्मी, मौसम में इस बदलाव का पड़ेगा दूरगामी प्रभाव

बीजिंग : मौसम के बदलते मिजाज सभी को हैरत में डाल रहे हैं। अब एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर यदि सही दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए तो साल 2100 आते-आते हो सकता है कि उत्तरी गोलार्द्ध (जिसमें भारत भी शामिल है) में गर्मी का मौसम छह महीने तक खींचे। ऐसे में तो एक बरस में मौसम चार की बात तो भूल ही जानी होगी। यदि ऐसा हुआ तो मौसम में इस बदलाव का कृषि, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर दूरगामी असर होगा।

जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स नामक जर्नल में प्रकाशित इस शोध अध्ययन के मुताबिक मौसम चक्र में सबसे ज्यादा बदलाव भूमध्यसागर क्षेत्र तथा तिब्बती पठार क्षेत्र में देखने को मिला है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि उत्तरी गोलार्द्ध में करीब 1950 के आसपास तक अनुमानित तौर पर चार मौसम तकरीबन नियत पैटर्न से आते-जाते थे। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण इनमें अनियमितता बढ़ती जा रही है। ऋतुओं की समयावधि और उनकी शुरुआत और बीतने का कोई निश्चित समय नहीं रह गया है। आने वाले समय में इसकी अनियमितता और भी बढ़ेगी।

शोध आलेख के मुख्य लेखक यूपिंग गुआन (चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस) के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी का मौसम लंबा तथा ज्यादा गर्म होता जा रहा है, जबकि सर्दी का मौसम छोटा और कम ठंड वाला होने लगा है।

शोधकर्ताओं ने उत्तरी गोलार्द्ध में 1952 से 2011 तक के चार मौसमों के बदलाव को लेकर दैनिक जलवायु संबंधी का आंकड़ों का विश्लेषण किया है। उन्होंने गर्मी की शुरुआत को सबसे गर्म 25 फीसद तथा इसी तरह सर्दी को 25 फीसद सबसे ठंड समयावधि के तौर परिभाषित किया।

यूएस में अवैध रुप से रह रहे भारतीयों के बड़े ठाटबाट, सालाना खर्च करते हैं 15.5 अरब डॉलर

वाशिंगटन : गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे भारतीयों की संख्या पांच लाख से ज्यादा है और यह लोग सालाना 15.5 अरब डॉलर खर्च करते हैं। इतना ही नहीं संघीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन को 2.8 अरब डॉलर का टैक्स भी अदा करते हैं। एक अमेरिकी थिंक टैंक द्वारा जारी रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है। खास बात यह है कि गैरकानूनी तरीके से रह रहे अनिवासी भारतीय उन शीर्ष तीन देशों के नागरिकों में शामिल हैं, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं।

यूएस में मैक्सिकों के 42 लाख लोग अवैध हैं : अमेरिका में मैक्सिकों के 42 लाख लोग अवैध रूप से रहते हैं। यह संख्या अमेरिका में एक करोड़ से अधिक गैरकानूनी तरीके से रहने वाले अनिवासियों की संख्या का 40.8 फीसद है। वर्ष 2019 में मैक्सिको के इन गैरकानूनी अनिवासियों ने 92 अरब डॉलर की कमाई की और संघीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन को 9.8 अरब डॉलर का टैक्स चुकाया।

अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से रहने वाले लोगों की बात करें तो मैक्सिको के बाद अल सल्वाडोर का नंबर आता है।

अल सल्वाडोर के 6,21,000 लोग अवैध : अल सल्वाडोर के 6,21,000 लोग गैरकानूनी तरीके से रहते हैं, जबकि भारत के 5,87,000, ग्वाटेमाला के पांच लाख चालीस हजार और होंडुरास के चार लाख लोग रहते हैं। खर्च करने के मामले में भारतीयों का स्थान दूसरा और वह कुल मिलाकर 15.5 अरब डॉलर का अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं।

प्रवासियों की पहली पंसद बना अमेरिका : संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में देश से बाहर रहने वाले लोगों की संख्या 18 मिलियन यानी एक करोड़ अस्सी लाख है। विदेशों में रहने के मामले में भारत दुनियाभर में पहले पायदान पर पहुंच गया है।

बजट में राहतों की भरमार, खुलेंगी 24 घंटे दुकानें व रेस्टोरेंट

• चंडीगढ़.ब्यूरो

पंजाब के वित्तमंत्री मनप्रीत बादल पंजाब विधानसभा में राज्य के 2021-22 में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। दरअसल फाल्गुन के महीने में मनप्रीत बादल ने चुनावी बजट से हर वर्ग पर राहत की बौछार करने की कोशिश की है। महिलाओं को बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी है तो कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का ऐलान किया गई है। बुजुर्गों, दिव्यांगों की पेंशन 750 रुपये से बढ़ाकर दुगनी कर दी गई है जबकि कोविड के कारण व्यापार का नुकसान उठाने वालों व्यापारियों को भी राहत मिली है और वे अब पूरा साल 24 घंटे अपनी दुकानें, संस्थान खोल सकते हैं। महाराष्ट्र के बाद ऐसा करने वाला पंजाब दूसरा राज्य बन गया है। इससे केरोना से लड़खड़ाए राज्य के आर्थिक हालत को सुधारने में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही राज्य में बुढ़ापा पेंशन को दोगुना कर दिया गया है। बजट में किसानों के लिए नई योजना 'कामयाब किसान-खुशहाल पंजाब' शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही पंजाब के कालेजों के विद्यार्थियों को निशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। महिलाओं को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 170 करोड़ रुपये रखे गए हैं। उन्होंने बजट में कर्मचारियों के लिए भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई से पहले नए वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी। दूसरी ओर, स्पीकर ने शिरोमणि अकाली दल के नौ विधायकों का सदन से निलंबन समाप्त कर दिया। अब वे कल बजट पर होने वाली बहस में हिस्सा ले सकेंगे।

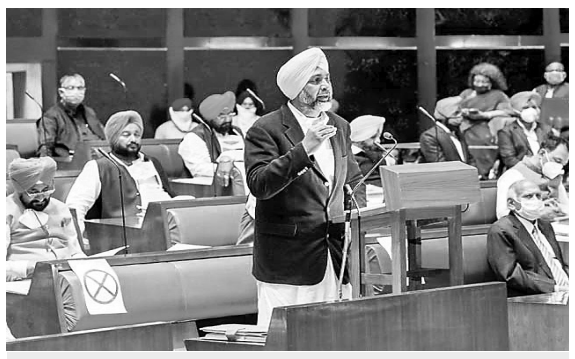

लागू होगा पे कमीशन

किसानों के लिए नई योजना

मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि पंजाब का कर्ज 31 मार्च तक 252880 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह 2021- 22 में बढ़ कर 273703 करोड़ रुपये हो जाएगा। वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि रिसोर्स गैप इस साल ज़ीरो रहेगा यानी सरकार के पास जितने पैसे हैं उतना ही खर्च होगा। किसानों की कर्जमाफी के लिए बजट में 10186 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा जारी करने का ऐलान किया।

जानें आमदनी और खर्च का ब्योरा

रुपया आएगा कैसे

राज्य के करों से आमदनी	-	28 पैसा
राज्य के गैर कर से आमदनी	-	06 पैसा
केंद्रीय ग्रांट	-	29 पैसा
सरकारी ऋण	-	28 पैसा
केंद्रीय कर में हिस्सा	-	09 पैसा

रुपया खर्च कैसे होगा

अन्य रेवेन्यू खर्च	-	32 पैसा
वेतन व अन्य भत्ते	-	20 पैसा
कर्ज के ब्याज की अदायगी	-	15 पैसा
पूंजीगत खर्च	-	10 पैसा
पेंशन व रिटायरमेंट लाभ	-	09 पैसा
पब्लिक डेबिट का पुनर्भुगतान	-	13 पैसा
लोन का एडवांस	-	01 पैसा

मेरिट में आने वाले बच्चों को फीस में छूट

वित्तमंत्री ने मेरिट में आने वाले बच्चों को फीस में छूट देने का भी ऐलान किया। उन्होंने अपनी राशन कार्ड योजना शुरू की। इसके तहत पांच किलो आटा भी मिलेगा। इसके लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट का थीम 'जय जवान नय किसान' दिया गया है। मनरेगा के लिए 400 करोड़ रुपये रखे हैं।

किसान कर्जमाफी के लिए 10186 करोड़ रुपये

वित्तमंत्री ने कहा कि खराब ट्यूबवेलों की मरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि मोहाली में रीजनल वायरोलॉजी सेंटर स्थापित होगा और केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य में किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रहेगी। इसके लिए बजट में 7000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अनुमानित राजस्व प्राप्ति 1,62,599 करोड़ और अनुमानित खर्च 1,68,015 रुपये

मनप्रीत बादल ने कहा कि सरकार का अनुमानित राजस्व 1,62,599 करोड़ होगा और अनुमानित खर्च 1,68,015 करोड़ होगा। बजट में कैंसर के पीड़ितों के लिए 150 करोड़ रुपये रखे गए हैं। कपूरथला व होशियारपुर में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 80 करोड़ अलॉट किए गए हैं। मलेरकोटला व गुरदासपुर में मेडिकल कॉलेज को अभी भारत सरकार से इजाजत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि होशियारपुर में कैंसर हस्पताल बनेगा।

उन्होंने कहा कि पटियाला सरकारी मेडिकल कालेज के बुनियादी सुधार के लिए 92 करोड़ का बजट रखा गया है। गुरदासपुर और मलेरकोटला में नए मेडिकल कालेज होंगे स्थापित।

बजट की खास बातें

- राज्य में दुकानें और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रह सकेंगे। कोरोना कारण बदहाल हुई अर्थ व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी।
- राज्य में महिलाओं और कालेज विद्यार्थियों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा।
- राज्य में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन दोगुनी की गई। पहले मिलती थी प्रति माह 750 रुपये और अब मिलेगी प्रति माह 1500 रुपये मिलेगी पेंशन।
- किसानों के लिए नई योजना ' कामयाब किसान-खुशहाल पंजाब' शुरू करने का ऐलान।
- किसानों को मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगा।
- किसान कर्जमाफी के लिए 10168 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- कर्मचारियों के लिए नए पे कमीशन (वेतन आयोग) की रिपोर्ट 31 मार्च तक आएगी। इसे 31 जुलाई से पहले घोषित कर दिया जाएगा।
- मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को फीस में छूट का ऐलान।
- नई राशन कार्ड योजना का भी घोषणा की गई। इसके तहत हर माह पांच किलो आटा मिलेगा।
- महिलाओं की सगुन स्कीम के तहत मिलने वाली राशि 51 हजार रुपये की गई। इससे पहले यह राशि 21 हजार रुपये थी।
- पंजाबी, हिंदी व उर्दू के बुजुर्ग लेखकों व कवियों को हर माह 15 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी।
- पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिह ने अपनी सरकार के अंतिम बजट को विधानसभा में रखने से पहले जो सात सूत्रीय 'एजेंडा 2022' पेश किया था, वित्तमंत्री मनप्रीत बादल उसे पूरा करते दिखाई पड़ रहे हैं। महिला, किसान, दुकानदार, युवा और अनुसूचित वर्ग को खुश करने पर फोकस करते हुए 1.62 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है।

- तीन कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन की छाप भी बजट पर दिखाई दे रही है। किसान कर्ज माफी की योजना को जारी रखते हुए उसके लिए 1186 करोड़ रुपये रखे गए हैं तो खेतिहर मजदूरों के लिए 526 करोड़ का आवंटन किया है। किसानों के लिए 'कामयाब किसान, खुशहाल पंजाब' नाम से नई योजना के तहत किसानों को सब्जियों, फलों की खेती और सहायक धंधों में लाने के लिए नए रिसर्च सेंटर बनाने, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इनोवेशन सेंटर स्थापित करने का एलान किया गया है।
- एससी वर्ग के लिए मुख्यमंत्री ने बेटियों के विवाह पर आशीर्वाद योजना में मिलने वाली शगुन की राशि को 21 हजार से बढ़ाकर 51 हजार कर दिया है। भाजपा के पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाने के एलान के बाद से कांग्रेस ने इस सेक्टर पर फोकस किया है। कपूरथला में बाबा भीम राव अंबेडकर म्यूजियम और गुरु रविदास की याद में होशियारपुर में चार साल से बन रहे स्मारक को पूरा करने का ऐलान किया। गरीबों को मिल रहे सस्ते अनाज योजना को आगे बढ़ाते हुए पंजाब ने अपनी भी नई योजना लांच की है जिसमें नौ लाख उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जो राष्ट्रीय आहार योजना में शामिल नहीं हैं।

महिलाओं के आशीर्वाद स्कीम के तहत अब 51000 रुपये दिए जाएंगे। पहले यह राशि 21 हज़ार रुपये थी।

उन्होंने कहा कि 1.13 लाख किसानों का 1186 करोड़ कर्ज और भूमिहीन मजदूरों का 526 करोड़ का कर्ज माफ के लिए 1712 करोड़ रुपये रखे गए हैं। कपूरथला में बाबा भीम राव के नाम पर म्यूजियम तैयार होगा। इस पर 100 करोड़ की लागत आएगी। फाजिल्का में गांव गोबिंदगढ़ में 10 करोड़ रुपये की लागत से सब्जियों का उत्कृष्ट सेंटर स्थापित होगा।

कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट 31 मार्च तक : मनप्रीत बादल ने कहा , कैग ने भी कहा कि सरकार वित्तीय रिफॉर्म के पथ पर है। उन्होंने बुढापा पेंशन 1500 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की। पहले यह 750 रुपये प्रतिमाह थी।

कुल बजट 168015 करोड़ रुपये का

इस बार बजट 168015 करोड़ रुपये का है। वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बजट पेश करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय के कब्रिस्तान बनाने के लिए पांच लाख की ग्रांट मिलेगी। इसके लिए बजट में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 3822 करोड़ रुपये का प्रावधान : वित्तमंत्री ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 3822 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कोविड से लड़ने के लिए साजो सामान पर पंजाब सरकार ने 1000 करोड़ रुपये खर्च किए। मेडिकल एजुकेश का बजट 1008 करोड़ रुपये होगा। पिछले साल से यह 85 फीसदी ज्यादा है।

मौजूदा कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का यह अंतिम बजट है। अगले साल 2022 में पंजाब विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में यह बजट चुनावी होने की संभावना थी। बजट में कैप्टन सरकार का चुनावी एजेंडा साफ तौर पर दिखा है।

हिंसा के दौरान इंटरनेट शटडाउन पर नहीं रहता केंद्र सरकार का कंट्रोल : गृह मंत्रालय

• नई दिल्ली.ब्यूरो

गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में इंटरनेट शटडाउन को लेकर एक सवाल का जवाब दिया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इंटरनेट बैन या इंटरनेट शटडाउन की स्थिति में इंटरनेट का कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में नहीं होता है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि साइबर स्पेस में काफी चुनौतियां हैं। यहां कोई भी सूचना काफी तेजी से वायरल होती है जिसके दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। केंद्र सरकार की ओर राज्यसभा में बताया गया कि किसी भी हिंसा या दंगे के दौरान जब इंटरनेट शटडाउन होता है तो उसका कंट्रोल राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के हाथ में होता है। देश में इंटरनेट का शटडाउन टेलीकॉम सर्विसेज (संशोधन) का अस्थायी निलंबन नियमावली 2020 के तहत होता है। 2020 में इंटरनेट शटडाउन से हुआ 2.5 बिलियन डॉलर भारत में साल 2020 में कई जगहों इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं। इससे देश को काफी नुकसान भी हुआ। इंटरनेट शटडाउन से देश को होने वाले नुकसान की रिपोर्ट हर साल टाप 10 वीपीएन पोर्टल पर जारी किया जाता है जिसके मुताबिक साल 2020 में भारत में इंटरनेट बैन होने से करीब 2.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है।

2020 में भारत में 75 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। इस दौरान कुल 1,655 घंटों तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं। रिपोर्ट में कहा गया था कि साल 2020 में पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद हुआ है।

एस.सी. विद्यार्थियों से सिर्फ़ ट्यूशन फीस ही ली जाये : डीसी

जालंधर. ब्यूरो : डिप्टी कमिश्नर जालंधर घनश्याम थोरी ने निजी शैक्षिक संस्थानों के मुखियों को कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप योजना अधीन दिए जाने वाले फंड्स का अपना 40 प्रतिशत हिस्सा जारी कर दिया गया है, इसलिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से सिर्फ़ ट्यूशन फीस ही ली जाये। ज़िले में पोस्ट मैट्रिक योजना का जायज़ा लेने के लिए बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी ने निजी शैक्षिक संस्थानों को कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से योग्य अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के खातों में योजना अधीन की जा रही अदायगी में से मेनटीनैंस अलाऊंस न वसूल किये जाएं। उन्होनें कहा कि कुछ संस्थानों में मेनटीनैंस अलाऊंस भी लिए जा रहे हैं जो कि असहनीय है।

पीएम मोदी ने सांसदों से कहा, **75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृत महोत्सव में हिस्सा लें**

आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर 12 मार्च से 75 स्थानों पर 75 सप्ताह का लंबा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया। इस बात की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दी। प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी ने सांसदों से कहा है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'अमृत महोत्सव' में हिस्सा लें।

युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लिया। संगठन के निष्ठावान पूर्व पदाधिकारियों को उनके अमूल्य योगदान और सेवाभाव से किये गए कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।

रंधावा ने 5 उम्मीदवारों को तरस के आधार पर नियुक्ति पत्र सौंपे

• चंडीगढ़ ब्यूरो

सहकारिता मंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा पंजाब राज कृषि विकास बैंक के नव-नियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए।

सहकारिता मंत्री स. सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने आज चण्डीगढ़ में पंजाब राज कृषि विकास बैंक के लिए नव-नियुक्त पांच उम्मीदवारों को तरस के आधार पर नियुक्ति पत्र सौंपे।

बैंक के मुख्यालय में हुए सादे समागम के दौरान सहकारिता मंत्री की तरफ से जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए उनमें नवजीत कौर पत्नी स्व. हरप्रीत सिंह (सहायक मैनेजर), करनवीर सिंह पुत्र स्व. राम सिंह (सहायक मैनेजर), गुरजिन्दर कोर पत्नी स्व. बलजीत सिंह (क्लर्क), अमृतपाल सिंह पुत्र स्व. बलकार सिंह (क्लर्क) और सन्दीप कुमार पुत्र स्व. इंद्रजीत (दफ़्तरी) शामिल थे।

इस मौके अपने संबोधन के दौरान सहकारिता मंत्री स. रंधावा ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य के सर्वपक्षीय विकास के साथ-साथ समाज के समूह वर्गों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिवार का पालन-पोषण करन वाले प्रमुख की मौत का कमी को तो पूरा नहीं किया जा सकता परन्तु आज उन परिवारों के वारिसों को विभिन्न पदों पर तैनात करके अपने परिवार के लिए जीविका का सहारा बनाने के लिए नियुक्ति पत्र बांटें गये हैं।

सहकारिता मंत्री ने नव-नियुक्त कर्मचारियों को मुबारकबाद देते हुये कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से इन उम्मीदवारों को तरस के आधार पर सरकारी नौकरी देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई गयी है और अब वह आशा करते हैं कि यह समूह कर्मचारी अपने-अपने दफ़्तरों में अपनी ड्यूटी ईमानदारी और तनदेही से निभाएंगे।

इस मौके पर रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं विकास गर्ग, पंजाब राज कृषि विकास बैंक के चेयरमैन कमलदीप सिंह और एम.डी. चरनदेव सिंह मान भी उपस्थित थे।

फ्रंट पेज का शेष...

आयुष्मान भारत योजना...

...उप्पल ने और विवरण देते हुए बताया कि प्राथमिक जाँच के दौरान यह बात सामने आई है कि ज़िला कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी कस्बे में चल रहे एक नामी अस्पताल (जाँच प्रभावित न हो इस कारण नाम नहीं दिया जा रहा) ने इस साल के दौरान करीब 1282 व्यक्तियों के इलाज के लिए कुल 4,43,98,450 रुपए (चार करोड़ तेतालिस लाख अट्ठावन हज़ार चार सौ पचास रुपए) का बीमा क्लेम किया गया, जिसमें से इस अस्पताल के 519 दावे रद्द हो गए और बाकी बचे मामलों में से कुल 4,23,48,050 रुपए (चार करोड़ तेईस लाख अड़तालिस हज़ार पचास रुपए) के दावे स्टेट हैल्थ अथॉरिटी पंजाब द्वारा पास किए गए हैं।

पास हुई इस राशि 4,43,98,450 रुपए में से अब तक 1,86,59,150 रुपए (एक करोड़ छियासी लाख उनसठ हज़ार एक सौ पचास रुपए) की रकम की अदायगी बीमा कंपनी 'इफको टोकियो' द्वारा उक्त अस्पताल को की जा चुकी है। जाँच अधीन अस्पताल की पोल खोलते हुए उन्होंने बताया कि इस नामी अस्पताल द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत एक मरीज़ के इलाज के बदले उसके परिवार के अन्य व्यक्तियों का दाख़िला अस्पताल में दिखा कर झूठे बीमा क्लेम हासिल किए गए हैं।

प्राथमिक जाँच के अनुसार परमजीत कौर निवासी गाँव टुरना ज़िला जालंधर तारीख़ 13.09.2019 को इस अस्पताल में पित्ताश्य की पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए दाख़िल हुई थी, परंतु कुछ निजी कारणों से उसकी तरफ से अपने पित्ताश्य की पथरी का ऑपरेशन नहीं करवाया गया और बिना ऑपरेशन करवाए अपने घर चली गई थी। परंतु इस अस्पताल द्वारा उक्त मरीज़ के ऑपरेशन का 22,000 रुपए का आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के अधीन फर्जी बिल तैयार करके इफको टोकियो से दावा हासिल कर लिया गया। इसी तरह के एक अन्य केस में सुखविन्दर कौर निवासी सिद्धूपुर पित्ताश्य की पत्थरियों का ऑपरेशन कराने के लिए इसी नामी अस्पताल में दाख़िल हुई।

उसने पंजाब सरकार द्वारा जारी हुआ अपना स्मार्ट हैल्थ कार्ड अस्पताल में दिया परंतु अस्पताल के संचालक ने कहा कि एक कार्ड के साथ आपका इलाज नहीं हो सकता, या तो आपको पहले 25000 रुपए नगद जमा करवाने होंगे या 6 से 7 स्मार्ट कार्ड लाकर दें, तभी इलाज शुरू हो सकता है। सुखविन्दर कौर के परिवार को मजबूरी में अपने परिवार के तीन अन्य सदस्यों के स्मार्ट कार्ड इस अस्पताल में जमा करवा दिए, जिसके बाद उक्त अस्पताल द्वारा सुखविन्दर कौर के पित्ताश्य की पथरी का इलाज शुरू किया गया। इस अस्पताल के प्रबंधकों ने अपनी घपलेबाज़ी को छिपाने के लिए सुखविन्दर कौर के पारिवारिक सदस्यों (जिनके हैल्थ स्मार्ट कार्ड लिए थे) को अस्पताल के बैड पर लेटाकर वीडियो भी बनाई गई और उनसे कोरे कागज़ों पर दस्तखत करवाए और कहा कि यदि कोई फ़ोन आए तो कहना कि हमारा ऑपरेशन हुआ है, जबकि उन तीनों को कोई बीमारी भी नहीं थी। जाँच के मुताबिक अस्पताल द्वारा सुखविन्दर कौर और उसके परिवार के सदस्यों का भी ऑपरेशन किया जाना है यह दिखा कर 25000/25000 हज़ार का दावा किया गया।

जिससे यह शक ज़ाहिर होता है कि इस अस्पताल द्वारा आयुष्मान भारत सेहत बीमा योजना में बड़े स्तर पर घोटाला किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में ज़िला जालंधर, होशियारपुर और कपूरथला के नामी प्राईवेट अस्पतालों द्वारा बड़े स्तर पर इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम देकर इफको टोकियो बीमा कंपनी से नकली क्लेम हासिल किए गए हैं और किए जा रहे हैं। प्राप्त आंकड़ों से और ठोस जानकारी के अनुसार जालंधर, होशियारपुर और कपूरथला ज़िले के 77 प्राईवेट अस्पतालों के 4,828 दावा इफको टोकियो हैल्थ इंशोरैंस कंपनी द्वारा पिछले एक साल के दौरान संदिग्ध होने पर रद्द किए गए हैं। इन रद्द किए गए दावों की कुल राशि 5,59,96,407 (पाँच करोड़ उनसठ लाख छयानवे हज़ार चार सौ सात रुपए) बनती है। इतने बड़े स्तर पर इन दावों का संदिग्ध होना विजीलैंस ब्यूरो की जाँच के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा जालंधर, होशियारपुर और कपूरथला ज़िले के 35 सरकारी अस्पतालों के 1,015 दावे इफको टोकियो हैल्थ इंशोरैंस कंपनी द्वारा पिछले एक साल के दौरान रद्द किए गए हैं।

इन रद्द हुए दावों की कुल राशि 52,06,500 (बावन लाख छह हज़ार पाँच सौ रुपए) बनती है। सरकारी अस्पतालों में किए गए इलाज के क्लेम रद्द होना भी अपने आप में हैरानी भरा है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में किए गए इलाज का क्लेम किसी व्यक्ति विशेष को न जाकर राज्य सरकार के खाते में जाता है। श्री उप्पल ने बताया कि इस जाँच के दौरान यह बात भी सामने आई है कि इफको टोकियो बीमा कंपनी द्वारा ज़िला जालंधर, होशियारपुर और कपूरथला के कई सरकारी अस्पतालों के बीमा क्लेम सम्बन्धी ज़िला डिप्टी मैडीकल कमिश्नरों और सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही के कारण भारी मात्रा में रद्द किए गए हैं, जिसका मुख्य कारण बीमा कंपनी द्वारा सरकारी अस्पतालों के क्लेम रद्द करके कम से कम राशि बतौर क्लेम सरकारी अस्पतालों के खातों में न डालना और अधिक से अधिक अनचाहा वित्तीय लाभ लेना हो सकता है।

ऐसा होने के कारण पिछले करीब एक साल के दौरान अब तक कुल 52,06,500 रुपए (बावन लाख छह हज़ार पाँच सौ रुपए) की राशि जोकि पंजाब सरकार को बतौर दावा मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली है और स्टेट हैल्थ अथॉरिटी की लापरवाही के कारण सरकारी अस्पतालों के कई क्लेम रद्द हो चुके हैं, जिस कारण उपरोक्त तीनों ज़िलों में ही केवल एक साल के दौरान पंजाब सरकार को करीब 52,06,500 रुपए (बावन लाख छह हज़ार पाँच सौ रुपए) के वित्तीय घाटे का अनुमान है। इसके अलावा अन्य प्राईवेट अस्पतालों द्वारा इस सेहत बीमा योजना के अधीन क्लेम किए गए करोड़ों रुपए भी संदिग्ध तौर पर जाँच के दायरे में हैं।

क्या है आयुष्मान भारत योजना वर्णन योग्य है कि तारीख़ 20.08.2019 को शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश के 10 करोड़ से ज़्यादा गरीब/ज़रूरतमंद ग्रामीण और शहरी परिवारों को मुफ़्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा इस योजना के लिए 60 प्रतिशत और राज्य सरकारों द्वारा 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता के तौर पर बतौर प्रीमियम इफको टोकियो कंपनी को दी जाती है। पंजाब राज्य में यह योजना सरबत सेहत बीमा योजना के अधीन चल रही है, जिसके अनुसार लगभग 1000 रुपए की रकम राज्य सरकार की तरफ से बतौर प्रीमियम प्रति परिवार इस बीमा कंपनी को सालाना अदा की जा रही है।

इस सम्बन्धी पंजाब सरकार द्वारा गरीब/ज़रूरतमंद परिवारों को स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है। इस स्मार्ट कार्ड के द्वारा उस व्यक्ति को या उसके परिवार के मैंबर को यदि कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वह इस स्कीम के अधीन अस्पताल में दाख़िल होकर 5,00,000 रुपए तक का इलाज मुफ़्त करवा सकता है। इस योजना की निगरानी स्टेट हैल्थ अथॉरिटी, पंजाब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कर रहा है।

जालंधर देहाती थानों के लिए 26 लाख रुपये का सामान खरीदा

• जालंधर. रवि

जिला जालंधर (देहाती) के समूह थानों में तैनात मुलाजिमों के सहूलतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक थानों को 1 फ्रीज, 1 वाटर डिस्पेंसर्स, 1 वाटर कूलर, 2 डाइनिंग टेबल समेत 10 कुर्सियां, 10 बेड, 10 गद्दे, दो भट्ठियां, 1 आंटे का ड्रम,स्टेशनरी, क्रॉकरी व 15 प्लास्टिक की कुर्सियां उपलब्ध करवाई गई है।

डीजीपी पंजाब दिनकर गुप्ता व आईजी पुलिस रणवीर सिंह खटड़ा की नेतृत्व में सीनियर पुलिस कप्तान डॉ. संदीप कुमार गर्ग द्वारा बुधवार को जिला जालंधर देहाती के समूह थानों के मैसों के लिए करीब 26 लाख रुपये का सामान खरीदा गया। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि थानों में तैनात पुलिस मुलाजिमों को किसी भी तरह की बुनियादी सहूलतों की दिक्कत पेश न आए।

SPORTS PLANET स्पोर्ट्स प्लैनेट

फिटनेस टेस्ट में फिर फेल हुआ ये गेंदबाज

टी-20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका

• नई दिल्ली.ब्यूरो

इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका लगा है। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती लगातार दूसरी बार फिटनेस टेस्ट पास करने में फेल वह सीरीज से बाहर हो गए हैं। वरुण चक्रवर्ती के अलावा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन का भी सीरीज के शुरुआती मैचों में खेलना संदिग्ध है।

टी नटराजन नेशनल क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में रिहैब की प्रक्रिया गुजर रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती लगातार दूसरी बार फिटनेस टेस्ट पास करने में नाकाम रहे हैं। इस स्पिनर को इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है।

वरुण चक्रवर्ती को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू का इंतजार है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भी उन्हें टीम में शामिल किया गया था, लेकिन चोट के वो बाहर हो गए थे।

वरुण आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के लिए खेलते हैं। पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्हें टीम इंडिया में जगह मिली है।

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज की शुरुआत 12 मार्च से हो रही है। सीरीज के सभी मुकाबले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे।

टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), केएल राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), युजवेंद्र चहल, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, टी. नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, नवदीप सैनी, शार्दुल ठाकुर।

लंबे ब्रेक के बाद भुवनेश्वर कुमार की टी20 टीम में वापसी

• नई दिल्ली.ब्यूरो

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण का मानना है कि इस साल टी20 विश्व कप में भारत के अभियान में भुवनेश्वर कुमार अहम भूमिका निभाएगा और इस तेज गेंदबाज के काम के बोझ के प्रबंधन को प्राथमिकता देने की जरूरत है। चोट के कारण लंबे ब्रेक के बाद भुवनेश्वर ने भारत की टी20 टीम में वापसी की।

उन्हें पिछले साल इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान जांघ की मांसपेशियों में चोट लगी थी जिसके कारण वह आईपीएल और फिर आस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हो गए थे। लक्ष्मण ने स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम 'क्रिकेट कनेक्टेड' में कहा, ''मुझे बेहद खुशी है कि भुवनेश्वर ने दोबारा फिटनेस हासिल कर ली क्योंकि वह भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण गेंदबाज है, विशेषकर सीमित ओवरों की क्रिकेट में।''

उन्होंने कहा, ''जसप्रीत बुमराह के अलावा भारतीय गेंदबाजी क्रम में अगर किसी को नई गेंद और डेथ ओवरों दोनों में गेंदबाजी का अनुभव है

तो वह भुवनेश्वर है।'' लक्ष्मण ने कहा, ''वह काफी महत्वपूर्ण सदस्य है, हमें भुवनेश्वर कुमार का ख्याल रखना होगा क्योंकि वह नवंबर में विश्व कप में काफी अहम भूमिका निभाने वाला है।'' उत्तर प्रदेश के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर ने अपना पिछला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला दिसंबर 2019 में खेला था। लक्ष्मण ने कहा, ''उसके शत प्रतिशत फिट रहने के लिए मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार के काम के बोझ और चोट के प्रबंधन को प्राथमिकता और अहमियत देनी चाहिए।''

लक्ष्मण को लगता है कि भुवनेश्वर को शुक्रवार से इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में दो से अधिक मुकाबले खेलने को नहीं मिलेंगे। लक्ष्मण ने रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज करने के लिए शिखर धवन पर विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल को तरजीह दी। उन्होंने कहा, ''दूसरे सलामी बल्लेबाज का चयन मुश्किल सवाल है। सीमित ओवरों के क्रिकेट में रोहित शर्मा का चुना जाना तय है। मैं लोकेश राहुल के साथ जाऊंगा क्योंकि पिछले कुछ महीनों और वर्षों में मुझे लगता है कि भारतीय टीम प्रबंधन ने जब भी लोकेश राहुल को सलामी बल्लेबाज के रूप में उतारा है तो उसने उस स्थान पर शानदार प्रदर्शन किया है।''

आईसीसी ने कर दिया आधिकारिक ऐलान, इस शहर में खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल

• नई दिल्ली.ब्यूरो

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आइसीसी ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के उद्घाटन सत्र के फाइनल का आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि टूर्नामेंट का फाइनल कब और कहां खेला जाएगा। आइसीसी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी दी है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला फाइनल मैच इंग्लैंड के साउथैंप्टन शहर के हैंपशायर बाउल में खेला जाएगा। पहले WTC का फाइनल लंदन के लॉर्ड्स में प्रस्तावित था, लेकिन आइसीसी और ईसीबी ने इसके वेन्यू को बदला है। हालांकि, अभी ये तय नहीं हुआ है कि 25 हजार की दर्शक क्षमता वाले इस स्टेडियम में कितने दर्शक मौजूद रहेंगे।

टेस्ट क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने के लिए आइसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत की थी। हालांकि, इस टूर्नामेंट का पहला ही सीजन विवादों में रहा, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के कारण एक झटके में आइसीसी

ने नया नियम लागू कर दिया और प्वाइंट्स टेबल में जो टीम टॉप पर थी वो तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। शुरुआत में आइसीसी ने ऐलान किया था कि अंकों के आधार पर जो टीम टॉप पर होंगी उनके बीच फाइनल खेला जाएगा, लेकिन बाद में जब कोरोना महामारी के कारण कुछ सीरीज स्थगित और कुछ सीरीज रद हो गईं तो फिर आइसीसी ने जीत प्रतिशत के हिसाब से प्वाइंट्स टेबल तैयार की थी और इस तरह भारत और न्यूजीलैंड की टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था।

आइसीसी ने अब जानकारी दी है और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की टिकट भी बेचनी शुरू कर दी हैं। आइसीसी के मुताबिक, 18 जून से 22 जून के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच साउथैंप्टन के हैंपशायर बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके लिए 23 जून का दिन रिजर्व डे है, अगर मैच के दौरान बारिश आती है तो फिर मैच 23 जून को भी खेला जाएगा।

हालांकि, पहले इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से इसे साउथैंप्टन शहर में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि इसी स्टेडियम के परिसर में एक शानदार होटल है, जिसमें इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बुक कर लिया है।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.